



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2014/माघ 29, 1935

No. 59]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2014/MAGHA 29, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 10 फरवरी, 2014

सं. टीएमपी/5/2014-वीओसीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास में बर्थ सं. I से VI और IX के लिए दरमानों की अधिसूचना के लिए मै0 आईएमसीओएलए क्रेन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/5/2014-वीओसीपीटी

मै0 आईएमसीओएलए क्रेन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक

कोरम :

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(फरवरी 2014 के 4थे दिन पारित)

यह मामला वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास में बर्थ सं. I से VI और IX के लिए दरमानों की अधिसूचना के लिए मै0 आईएमसीओएलए क्रेन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव से सम्बंधित है।

2.1. मै0 आईएमसीओएलए क्रेन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (आईसीसीपीएल) ने अपने पत्र सं. आईएमसीओएलए/वीओसीपीटी/43/ 2013-14 दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 द्वारा इस प्राधिकरण से अपने दरमान अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। आईसीसीपीएल द्वारा अपने पत्र में कही गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:-

- (i) आईसीसीपीएल वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) में निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन आधार पर बर्थों I से VI और IX में अवसंरचना के अभियांत्रिक प्रहस्तन को अपग्रेड करने के लिए रियायतप्राप्तकर्ता है।
- (ii) उक्त परियोजना के लिए प्रशुल्क निर्धारण मामला सं. टीएमपी/16/2010-टीपीटी दिनांक 23 जुलाई, 2010 द्वारा किया गया था।
- (iii) इस परियोजना के 10 जनवरी, 2014 तक शुरू होने की उम्मीद है।

2.2. प्रस्तावित दरमान का मसौदा भेजते समय, आईसीसीपीएल ने अपने ऊपर संदर्भित पत्र द्वारा इस प्राधिकरण से अपने दरमान को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने का अनुरोध किया था।

3.1. चूंकि आईसीसीपीएल ने अपने द्वारा वीओसीपीटी के साथ किए गए रियायत अनुबंध (सीए) की प्रमाणित प्रति नहीं भेजी थी, इसलिए आईसीसीपीएल से हमारे पत्र दिनांक 2 जनवरी, 2014 द्वारा सीए भेजने का अनुरोध किया गया था।

3.2. प्रत्युत्तर में, आईसीसीपीएल ने अपने पत्र सं. आईएमसी/वीओसीपीटी/44/2013-14 दिनांक 2 जनवरी 2014 द्वारा विषय प्रस्ताव के लिए वीओसीपीटी के साथ किए गए रियायत अनुबंध की प्रति भेजी है।

4.1. आईसीसीपीएल के पत्र दिनांक 30 दिसम्बर 2013 की प्रति हमारे पत्र दिनांक 2 जनवरी 2014 द्वारा वीओसीपीटी, लाइसेंसदाता, को उसकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अग्रप्रेषित की गई थी। वीओसीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2014 द्वारा आईसीसीपीएल द्वारा प्रस्तावित मसौदा दरमान पर निम्नलिखित टिप्पणियां भेजी थी:

- (i) टीएमपी दिशानिर्देश, 2008 के खंड 2.9.1 के अनुसार जमा किया गया मसौदा दरमान आधार दर पर 17.63 प्रतिशत का योग्य वृद्धि कारक लागू करते हुए अधिसूचना सं. टीएमपी/16/2010-टीपीटी दिनांक 9 अगस्त, 2010 द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक दरमान से सत्यापित किया गया है। ब्रेक-बल्क कार्गो के लिए अनुसूची-2 के अधीन एक टिप्पणी की चूक के सिवाय सभी दरें तथा निबंधन एवं शर्तें सही हैं।

4.2. वीओसीपीटी ने इस प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 23 जुलाई 2010 में यथा-निर्धारित ब्रेक-बल्क कार्गो के लिए अनुसूची-2 के अधीन टिप्पणी को पुनः प्रस्तुत किया है, जिसे नीचे दिया गया है:-

“**टिप्पणी:** ऊपर दर्शाई गई संवर्धनात्मक अधिकतम दरों की गणना करने के लिए, आधार दर में प्रथम पांच हजार टन के लिए 105 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। 7000 टन से अधिक की दर की गणना करने के लिए भी इसी कार्यपद्धति को अंगीकृत किया जा सकता है। इसी प्रकार, 5000 टन से कम कार्यनिष्पादन के लिए अधिकतम दरें आधार दर में तदनुसार कटौती करते हुए परिकलित की जाएंगी।”

5. हमारे अनुरोध में आईसीसीपीएल द्वारा प्रेषित रियायत अनुबंध के अनुसार, वीओसीपीटी को मै0 आईएमसीओएलए क्रेन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (आईसीसीपीएल) को बीओओटी आधार पर अभियांत्रिक प्रहस्तन अवसंरचना के अपग्रेडेशन की परियोजना अवार्ड की थी। वीओसीपीटी के साथ रियायत अनुबंध पर 24 मई, 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह अनुबंध रियायत प्रदान किए जाने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध है।

6.1. अपक्रंट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.1 के अनुसार, निजी प्रचालक महापत्तन न्यास अधिनियम (एमपीटी) अधिनियम की धारा 48 के अधीन यथा-अपेक्षित वाणिज्यिक प्रचालनों की शुरुआत से पहले उसके प्रचालनों पर लागू अधिकतम दरों को समाहित किए दरमान की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण के पास जाएगा और 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.2 के अनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने वाले दरमान पत्तन के लिए निर्धारित प्रशुल्क सीमाओं के अनुसार होंगे और खंड 2.8 में स्पष्ट किए गए सूचकांकन के अधीन बोली दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। ऐसे दरमान और शर्तों के विवरण महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 द्वारा यथा-अपेक्षित भारत सरकार के राजपत्र में इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

6.2. महापत्तन न्यासों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए अपक्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2008 के खंड 2.8 के अनुसार, प्रशुल्क सीमाएं मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएंगी परन्तु 1 जनवरी, 2008 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही सूचकांकित किया जाएगा, और समायोजित प्रशुल्क प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा।

6.3. अपक्रंट प्रशुल्क के लिए आधार वर्ष और 1 अप्रैल, 2013 से तदनुसूची वार्षिक वृद्धि के बारे में हमारे पत्र सं. टीएमपी/12/2009-विविध दिनांक 2 अप्रैल, 2013 द्वारा वीओसीपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को पहले ही संप्रेषित कर दिया गया था।

6.4. संदर्भित सुविधा के लिए अपक्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते हुए अपक्रंट प्रशुल्क आदेश दिनांक 23 जुलाई 2010 के दरमानों के खंड 3 (अनुसूची (2) के लिए सामान्य टिप्पणी) के अनुसार, प्रशुल्क सीमाओं को 1 जनवरी, 2010 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले डब्ल्यूपीआई में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाना चाहिए था। तदनुसार, संदर्भित मामले में लागू किया जाने वाला वृद्धि कारक दरमान के खंड 3 के साथ पठित हमारे पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 2013 के अनुसार 17.63 प्रतिशत है।

7.1. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

- (i) इस प्राधिकरण ने वीओसीपीटी में बीओओटी आधार पर अभियांत्रिक प्रहस्तन उपस्करों के प्रचालन के लिए अपक्रंट प्रशुल्क के निर्धारण हेतु वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव के आधार पर अपक्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते हुए एक आदेश सं. टीएमपी/16/2010-टीपीटी दिनांक 23 जुलाई, 2010 पारित किया था जिसे राजपत्र सं. 201 द्वारा 12 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। वीओसीपीटी में बीओओटी आधार पर बर्थ सं. I से VI और IX में अभियांत्रिक प्रहस्तन उपस्करों के अपग्रेडेशन की परियोजना अवार्ड की है और 10 वर्षों की अवधि के लिए 24 मई, 2013 को एक रियायत अनुबंध किया है।
- (ii) जैसाकि पहले बताया गया है, अपक्रंट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.9.1 निजी प्रचालक से अपेक्षा करता है कि वह वाणिज्यिक प्रचालनों की शुरुआत से पहले उसके प्रचालनों पर लागू अधिकतम दरों के साथ दरमान की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण के पास जाना होगा। तदनुसार, आईसीसीपीएल ने 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन यथा-अपेक्षित दरमान की अधिसूचना के लिए एक अनुरोध के साथ इस प्राधिकरण का रुख किया है।
- (iii) जैसाकि आईसीसीपीएल द्वारा बताया गया है, प्रचालक उम्मीद करता है कि वाणिज्यिक प्रचालन 10 जनवरी, 2014 से शुरू होंगे। आईसीसीपीएल द्वारा प्रतिवेदित स्थिति पर विश्वास करते हुए, यह प्राधिकरण जुलाई, 2010 में अनुमोदित दरमानों की अधिसूचना के लिए आईसीसीपीएल के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के लिए प्रवृत्त है बशर्ते दरों के सूचकांकन के संदर्भ में डब्ल्यूपीआई के लिए अनुमोदित 60 प्रतिशत की सीमा तक समायोजन किया जाएगा।

- (iv) 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.2 के अनुसार, खंड 2.9.1 के अनुसार निजी प्रचालक के लिए इस प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने वाले दरमान पत्तन के लिए निर्धारित प्रशुल्क सीमाओं के अनुसार होने चाहिए और बोली दस्तावेज में शामिल किया जाना चाहिए, परन्तु पहले यथा स्पष्ट किए गए सूचकांकन के अधीन। वीओसीपीटी तथा आईसीसीपीएल के बीच हुए रियायत अनुबंध (सी.ए.) का अनुच्छेद 8.1 रियायत अनुबंध के अनुसार बहुउद्देशीय बर्थ सं. I से VI और IX में प्रशुल्क की वसूली को शासित करता है। लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 8.1 के अनुसार, रियायतप्राप्तकर्ता अर्थात् आईसीसीपीएल परिशिष्ट-12 रूप में संलग्न की गई प्रशुल्क अधिसूचना के अनुसार परियोजना सुविधाओं तथा सेवाओं के उपयोक्ताओं से प्रशुल्क वसूल करने के लिए हकदार होगा। यह देखा गया है कि सी.ए. के साथ संलग्न परिशिष्ट - 12 इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/16/2010-टीपीटी दिनांक 23 जुलाई, 2010 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अप्रकट प्रशुल्क के लिए संदर्भ देता है। यह प्रशुल्क आदेश सं. टीएमपी/50/2011-वीओसीपीटी दिनांक 19 जनवरी, 2012 के लिए भी संदर्भ देता है।
- (v) रियायत अनुबंध के परिशिष्ट-12 में उल्लिखित पत्र आदेश दिनांक 19 जनवरी, 2012 के सम्बंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वीओसीपीटी ने 120 टन क्षमता के एचएमसी के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु पृथक प्रस्ताव दाखिल किया था। तथापि, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/50/2011-वीओसीपीटी दिनांक 19 जनवरी, 2012 द्वारा उक्त वीओसीपीटी प्रस्ताव को अस्वीकार किया है और आदेश दिया है कि आदेश सं. टीएमपी/16/2010-टीपीटी दिनांक 23 जुलाई, 2010 में निर्धारित अप्रकट प्रशुल्क 23 जुलाई 2010 के उक्त आदेश के पैरा 9.1 में यथा उल्लिखित प्रशुल्क के वार्षिक सूचकांकन के अधीन विनिर्दिष्ट पांच वर्षों के दौरान वीओसीपीटी में एचएमसी को शामिल करने के लिए माल होल्ड करता है। अतः, सी.ए. के परिशिष्ट-12 में दिए गए आदेश सं. टीएमपी/50/2011-वीओसीपीटी दिनांक 19 जनवरी, 2012 के संदर्भ में, आईसीसीपीएल के लिए दरमानों की अधिसूचना के लिए प्रासंगिक दिखाई नहीं देती है।
- (vi) 2008 के दिशानिर्देशों के खंड 2.8 के अधीन यथा-अपेक्षित आदेश दिनांक 23 जुलाई, 2010 द्वारा निर्धारित अप्रकट प्रशुल्क के सूचकांकन के संदर्भ में, 17.63 प्रतिशत का वृद्धि कारक जुलाई, 2010 में अधिसूचित प्रशुल्क सीमाओं पर लागू किया गया है। आईसीसीपीएल ने उक्त प्रशुल्क आदेश में यथा निर्धारित दरों को लागू करने को शासित करने वाली शर्तों के साथ, जुलाई 2010 में अधिसूचित प्रशुल्क सीमाओं पर 17.63 प्रतिशत का वृद्धि कारक लागू करते हुए मसौदा प्रस्तावित दरमान तैयार किया है। यह जुलाई 2010 के आदेश द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क मर्दे हैं जो लागू वृद्धि कारक को लागू करने के मद्देनजर बदलाव किया जाना है। अनुवर्ती वर्षों के लिए भी, जनवरी 2010 और प्रासंगिक वर्ष के जनवरी के बीच आने वाले डब्ल्यूपीआई के 60 प्रतिशत की सीमा तक सूचकांकन आदेश सं. टीएमपी/16/2010-टीपीटी दिनांक 23 जुलाई, 2010 द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क के संदर्भ में होना चाहिए और इस आदेश में अनुमोदित सूचकांकित दरमान के संदर्भ में नहीं होना चाहिए। अतः आदेश दिनांक 23 जुलाई, 2010 में अनुमोदित सामान्य टिप्पणी बनाए रखते हुए आईसीसीपीएल द्वारा प्रस्तावित अनुसूची (2) के लिए सामान्य टिप्पणी यह स्थिति स्पष्ट करते हुए उपयुक्ततः संशोधित की गई है। यह 2008 के दिशानिर्देशों के अधीन शासित अन्य बीओटी प्रचालकों, जिन्होंने प्रचालन शुरू किए हैं, के दरमानों में निर्धारण के अनुसार है। आदेश दिनांक 23 जुलाई, 2010 के दरमान में यथा-अनुमोदित दरों को लागू करने को शासित करने वाली सभी अन्य शर्तें बनाए रखी गई हैं।
- (vii) जैसाकि वीओसीपीटी द्वारा सही उल्लेख किया गया है, आईसीसीपीएल ने अपने प्रस्तावित मसौदा दरमान में, जुलाई, 2010 के आदेश में मुख्य अनुसूची 2 के अधीन ब्रेक-बल्क कार्गो (स्टील और बैग कार्गो) के लिए हारबर मोबाइल क्रेनों के किराये के लिए प्रभारों की अनुसूची (II) के नीचे निर्धारित की गई संवर्धनात्मक अधिकतम दरों की गणना को शासित करने वाली एक टिप्पणी शामिल नहीं की है। ब्रेक बल्क कार्गो के लिए अनुसूची-II के अधीन टिप्पणी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-
- “टिप्पणी: ऊपर दर्शाई गई संवर्धनात्मक अधिकतम दरों की गणना करने के लिए, आधार दर में प्रथम पांच हजार टन के लिए 105 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। 7000 टन से अधिक की दर की गणना करने के लिए भी इसी कार्यपद्धति को अंगीकृत किया जा सकता है। इसी प्रकार, 5000 टन से कम कार्यनिष्पादन के लिए अधिकतम दरें आधार दर में तदनुसार कटौती करते हुए परिकलित की जाएंगी।”
- इस प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 23 जुलाई, 2010 में निर्धारित उक्त टिप्पणी इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आईसीसीपीएल हेतु दरमान में शामिल की गई है।
- (viii) 2008 के दिशानिर्देशों के खंड 3.8.5 के अनुसार, यदि दरमानों और शर्तों के विवरण के स्पष्टीकरणों अथवा निवर्चन की अपेक्षा करते हुए कोई प्रश्न उठता है तो यह मामला इस प्राधिकरण को भेजा जाएगा और इस सम्बंध में इसका निर्णय प्रचालक पर बाध्यकारी होगा।
- (ix) आईसीसीपीएल से यह उम्मीद की जाती है कि वह कम से कम बोली दस्तावेजों/रियायत अनुबंध में दिए गए कार्यनिष्पादन प्रतिमानों के अनुसार निष्पादन करे। आईसीसीपीएल के वास्तविक कार्यनिष्पादन की इस प्राधिकरण द्वारा अनुवीक्षण किया जाएगा। यदि सेवा की गुणवत्ता के सम्बंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो यह प्राधिकरण ऐसे आरोप की जांच करेगा और अपने निर्णय वीओसीपीटी को अग्रेषित करेगा। यदि आईसीसीपीएल के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी होगी तो वीओसीपीटी रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा।
- (x) टर्मिनल में वाणिज्यिक प्रचालन के दौरान, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर, आईसीसीपीएल को यह निदेश दिया जाता है कि पूर्ववर्ती तीन महीनों के दौरान बर्थ सं. I से VI और IX में भौतिक तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट वीओसीपीटी के माध्यम से इस प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाए।

7.2. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण वीओसीपीटी में आईसीसीपीएल द्वारा प्रचालित किए जाने वाले बर्थ सं. I से VI और IX में अभियांत्रिक प्रहस्तन उपस्करों के प्रचालन के लिए दरमान अनुमोदित करता है जिसे अनुबंध रूप में संलग्न किया गया है।

7.3. आईसीसीपीएल के लिए अधिसूचित दरमान वीओसीपीटी में आईसीसीपीएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालनों की शुरुआत की तारीख से प्रभावी होंगे।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

## अनुबंध

आईएमसीओएलए क्रेन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड  
दरमान

## 1.1. परिभाषाएँ – सामान्य

इस दरमान में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:-

- (i) “तटीय पोत” का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत होगा।
- (ii) “विदेशगामी पोत” का अर्थ तटीय पोत से इतर कोई पोत होगा।
- (iii) “दिवस” का अर्थ एक दिन के प्रातः 6 बजे से शुरू होकर अगले दिन प्रातः 6 बजे तक समाप्त होने वाली अवधि होगी।

## 1.2. सामान्य निबंधन एवं शर्तें

- (i) (क) पीओएल, लौह अयस्क और लौह गुट्टिकाओं तथा ताप कोयला सहित कच्चे तेल से इतर सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधित प्रभार सामान्य कार्गो संबंधित प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।  
(ख) कार्गो संबंधित प्रभारों के मामले में, रियायती दरें जलयान तट स्थानांतरण के लिए सभी प्रासंगिक प्रहस्तन प्रभारों पर वसूल की जानी चाहिए।  
(ग) विदेशी पत्तन से कार्गो जो भारतीय पत्तन “ख” को अनुवर्ती पोतांतरण हेतु भारतीय पत्तन “क” पर पहुंचता है अपने तटीय नौचालन के लिए प्रासंगिक रियायती प्रभार वसूल किए जाएंगे। अन्य शब्दों में, तटीय नौचालन के लिए अनुमत पोतों द्वारा भारतीय पत्तनों से/को कार्गो रियायत के लिए पात्रता प्राप्त करेगा।  
(घ) तटीय कार्गो पोतों के लिए प्रभार भारतीय रूप में मूल्यवर्गित और संग्रहीत किया जाएगा।
- (ii) विलंबित भुगतानों/वापसियों पर ब्याज:  
(क) उपयोक्ता को इस दरमान के अधीन विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज अदा करना होगा। इसी तरह, टर्मिनल प्रचालक को विलंबित वापसियों पर दंडात्मक ब्याज अदा करना होगा।  
(ख) दंडात्मक ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी।  
(ग) वापसियों पर विलंब सेवाओं के पूरा होने की तारीख के 20 दिन बाद से अथवा उपयोक्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर, जो भी बाद में हो, परिगणित किया जाएगा।  
(घ) उपयोक्ताओं द्वारा भुगतानों में विलंब टर्मिनल प्रचालक द्वारा बिलों को दिए जाने की तारीख के 10 दिन बाद से परिगणित किया जाएगा। तथापि, यह प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां भुगतान सेवाएं प्राप्त करने से पहले किया जाता है जहां प्रभारों का अग्रिम भुगतान दरमान में एक शर्त के रूप में निर्धारित किया जाता है।
- (iii) सभी परिगणित प्रभार प्रत्येक बिल के सकल जोड़ पर अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किए जाएंगे।
- (iv) वापसी के दावों पर तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि वापसी-योग्य राशि रु0 100 अथवा अधिक न हो। इसी तरह, टर्मिनल प्रचालक कोई अनुपूरक अथवा प्रभार बिलों के अधीन मांग नहीं करेगा, यदि टर्मिनल की वजह से राशि रु0 100 अथवा कम हो।
- (v) (क) इस दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं; इसी प्रकार, रियायतें और छूट निम्नतम स्तर हैं। टर्मिनल प्रचालक, यदि वह ऐसा चाहे तो, निम्नतर दरें वसूल कर सकता है और/अथवा उच्चतर रियायतें और छूट प्रदान कर सकता है।  
(ख) टर्मिनल प्रचालक, यदि वह ऐसा चाहे तो, दरमान में निर्धारित दरों के कार्यान्वयन पर शासित निर्धारित शर्तों को युक्तिसंगत भी बना सकता है यदि युक्तिकरण से उपयोक्ताओं को दर प्रति इकाई में राहत मिलती है और दरमान में निर्धारित इकाई दरें अधिकतम स्तर से अधिक नहीं हों।  
(ग). टर्मिनल प्रचालक ऐसी निम्नतर दरें और/अथवा ऐसी दरों को लागू करने को शासित करने वाली शर्तों के युक्तिकरण को अधिसूचित करेगा बशर्ते नई निर्धारित दरें टीएएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक नहीं होंगी।
- (vi) उपयोक्ताओं को टर्मिनल प्रचालक पर आरोप्य उपयुक्त स्तर से अधिक विलंबों के लिए प्रभार अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

## 2. हारबर मोबाइल क्रेनों के किराये के लिए प्रभार:

## (I) शुष्क बल्क कार्गो के लिए

औसत दैनिक क्रेन कार्यनिष्पादन (मीट्रिक टनों में)	दर प्रति टन (रु0 में)	
	विदेशी	तटीय
9500-10499	29.69	17.81
10500-11499	31.43	18.86

11500-12499	33.18	19.91
12500	34.92	20.95
12501-13500	36.67	22.00
13501-14500	38.41	23.04
14501-15500	40.15	24.09

**टिप्पणी :** ऊपर दर्शाई गई संवर्धनात्मक अधिकतम दरों की गणना करने के लिए, प्रथम पांच हजार टनों के लिए आधार दर में 105 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी और 2रे हजार टनों के लिए इस दर में आधार दर में 110 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। तीसरे हजार टनों के लिए दर आधार दर में 115 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए निर्धारित किए गए थे। 15500 टनों से अधिक दर की गणना करने के लिए भी इसी कार्यपद्धति को अंगीकृत किया जाएगा। इसी तरह 9500 टनों से कम कार्यनिष्पादन के लिए अधिकतम दरें आधार दर में तदनुसार कटौती करते हुए गणना की जाएगी।

## (II) ब्रेक-बल्क कार्गो के लिए :

### (क) स्टील और बेग कार्गो

औसत दैनिक क्रेन कार्यनिष्पादन (मीट्रिक टनों में)	अधिकतम दर प्रति टन (रु० में)	
	विदेशी	तटीय
5000-5999	65.04	39.02
6000	68.46	41.08
6001-7000	71.88	43.13

**टिप्पणी :** ऊपर दर्शाई गई संवर्धनात्मक अधिकतम दरों की गणना करने के लिए, आधार दर में प्रथम पांच हजार टनों के लिए 105 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। 7000 टन से अधिक की दर की गणना करने के लिए भी इसी कार्यपद्धति को अंगीकृत किया जाएगा। इसी प्रकार 5000 टन से कम कार्यनिष्पादन के लिए अधिकतम दरें आधार दर में तदनुसार कटौती करते हुए परिकलित की जाएंगी।

### (ख) अन्य

औसत दैनिक क्रेन कार्यनिष्पादन (मीट्रिक टनों में)	अधिकतम दर प्रति टन (रु० में)	
	विदेशी	तटीय
2750-3749	104.11	62.47
3750	109.60	65.76
3751-4750	115.08	69.05

**टिप्पणी:** ऊपर दर्शाई गई संवर्धनात्मक अधिकतम दरों की गणना करने के लिए, आधार दर में प्रथम पांच हजार टनों के लिए 105 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। 4750 टन से अधिक की दर की गणना करने के लिए भी इसी कार्यपद्धति को अंगीकृत किया जाएगा। इसी प्रकार, 2750 टन से कम कार्यनिष्पादन के लिए अधिकतम दरें आधार दर में तदनुसार कटौती करते हुए परिकलित की जाएंगी।

### टिप्पणियां :

(i) औसत बर्थ-दिवस आउटपुट की गणना के लिए सूत्र निम्नवत् है:

एचएमसी द्वारा लादी/उतारी गई कुल मात्रा

----- X 24 घंटे

शुरुआत से पूरा करने तक पोत से लिया गया कुल समय

- (ii) कार्गो की लदाई/उतराई के शुरु होने से पूरा होने तक पोत के लिए औसत बर्थ-दिवस आउटपुट के अनुसार, क्रेन किराया प्रभार की उपयुक्त दर लादे गए/उतारे गए कार्गो की पूर्ण मात्रा के लिए पत्तन उपयोक्ताओं से वसूल करने के लिए चुनी जाएगी।
- (iii) यदि एक एचएमसी दूसरे एचएमसी अथवा ईएलएल क्रेनों के साथ कार्य करता है, क्रेन के लिए बर्थ-दिवस आउटपुट एचएमसी के लदाई मीटर द्वारा यथा रिकार्ड की गई मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- (iv) एक घंटे से अधिक के लिए क्रेन खराब होने के मामले में पोत के बर्थ छोड़ने तक, एचएमसी द्वारा प्रहस्तित मात्रा क्रेन कार्य घंटों द्वारा विभाजित ब्रेक-डाउन से पहले लादे गए/उतारे गए कार्गो और 24 से गुणा को लेखा में लेते हुए निर्धारित की जाएगी।
- (v) एचएमसी पर अनारोप्य कारणों से एक ही बार में दो घंटों से अधिक के लिए एचएमसी के परिचालन को रोकने के मामले में, पोत में क्रेन परिचालन का कुल समय की गणना करते समय उपयुक्त भत्ता क्रेन के लिए स्वीकार्य होगा। 2 घंटों से कम के लिए एचएमसी का रूकना उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विचारार्थ नहीं लिया जाएगा। एचएमसी पर आरोप्य रुकावटों के लिए कोई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। एचएमसी की गणना के दौरान लदाई/उतराई परिचालनों में सभी विराम दैनिक पोत निष्पादन रिपोर्ट में टीपीटी अधिकारियों अथवा टीपीटी द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रमाणित किए जाने अपेक्षित हैं।

- (vi) यदि पोत का स्थानांतरण एचएमसी की खराबी/गैर निष्पादन की वजह से जरूरी हो जाता है, बर्थ से लंगरगाह तक स्थानांतरण प्रभार रु0 1,00,000 (रुपये एक लाख केवल) के जुर्माने के अलावा क्रेन परिचालक से वसूल किए जाएंगे। ऐसे वसूल किए गए स्थानांतरण प्रभार पोत के एजेंट को वापस किए जाएंगे जब जुर्माना पत्तन द्वारा रखा जाएगा।
- (vii) औसत आउटपुट पर विवाद के मामले में, पत्तन न्यास का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

**3. उपर्युक्त अनुसूची (2) के लिए सामान्य टिप्पणी :**

आईएमसीओएलए क्रेन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के दरमानों में निर्धारित प्रशुल्क सीमाएं इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/16/2010-टीपीटी दिनांक 23 जुलाई, 2010 द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क पर विचार करते हुए और 1 जनवरी, 2010 तथा प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत तक सीमा तक सूचकांकन लागू करते हुए विचार किया गया है। अनुवर्ती वर्षों के लिए भी, आदेश सं. टीएमपी/16/2010-टीपीटी, दिनांक 23 जुलाई, 2010 में अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा परन्तु 1 जनवरी, 2010 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के केवल 60 प्रतिशत की सीमा तक। प्रशुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक लागू होंगी।

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th February, 2014

**No. TAMP/5/2014-VOCPT.**—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes the proposal received from M/s. IMCOLA Crane Company Private Limited for notification of Scale of Rates for Berth Nos. I to VI & IX at V.O. Chidambaranar Port Trust as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

**Case No. TAMP/5/2014-VOCPT**

M/s. IMCOLA Crane Company Private Limited

...

**Applicant**

**QUORUM:**

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on 4th day of February, 2014)

This case relates to the proposal received from M/s. IMCOLA Crane Company Private Limited for notification of Scale of Rates for Berth Nos. I to VI & IX at V.O. Chidambaranar Port Trust.

2.1. M/s. IMCOLA Crane Company Private Limited (ICCPL) vide its letter No.IMCOLA/VOCPT/43/2013-14 dated 30th December, 2013 has requested this Authority to notify its Scale of Rates. The main points made by ICCPL in its letter are summarized below:

- (i) ICCPL is the concessionaire for upgradation of mechanical handling infrastructure at berths I to VI & IX on Build, Own and Operate basis at V.O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT).
- (ii) The tariff setting for the said project was undertaken vide case No.TAMP/16/2010-TPT, dated 23rd July, 2010.
- (iii) The project is expected to be commissioned by 10th January, 2014.

2.2. Furnishing the draft of the proposed Scale of Rates, the ICCPL vide its above referred letter has requested this Authority to notify its Scale of Rates (SoR) in the Gazette of India.

3.1. Since ICCPL had not furnished the authenticated copy of the Concession Agreement (CA) entered by it with the VOCPT, the ICCPL was requested vide our letter dated 2 January 2014 to furnish the CA.

3.2. In response, the ICCPL vide its letter No. IMC/VOCPT/44/2013-14 dated 2 January 2014 has furnished a copy of Concession Agreement entered by it with the VOCPT for the subject project.

4.1. A copy of ICCPL's letter dated 30 December 2013 was forwarded to the VOCPT, Licensor, vide our letter dated 2 January 2014 seeking its comments. The VOCPT vide its letter dated 23 January 2014 has furnished following comments on the draft SOR proposed by ICCPL:

- (i) The draft SOR submitted as per clause 2.9.1 of TAMP guidelines 2008 is verified with the relevant SOR approved by the Authority vide Notification No. TAMP/16/2010-TPT dated 9 August 2010 applying eligible escalation factor of 17.63% on the base rates. All the rates and terms and conditions are in order except the omission of one Note under Schedule-II for Break-bulk cargo.

4.2. The VOCPT has reproduced the Note under Schedule II for Break-bulk cargo as prescribed by this Authority in the Order dated 23 July 2010, which is given below:

**“Note:** To calculate the incremental ceiling rates as shown above, the base rate was enhanced to 105% for first thousand tonnes. The same methodology shall also be adopted to calculate the rate beyond 7000 tonnes. Likewise, ceiling rates for performance below 5000 tonnes shall be calculated by reducing the base rate accordingly.”

5. As per the Concession Agreement furnished by ICCPL at our request, the VOCPT has awarded the project of Upgradation of Mechanical Handling Infrastructure on BOOT basis to M/s. IMCOLA Crane Company Private Limited (ICCPL). The Concession Agreement with VOCPT has been signed on 24 May 2013 and the agreement is valid for a period of 10 years from the date of award of concession.

6.1 As per Clause 2.9.1. of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff, the private operator shall approach this Authority for notification of Scale of Rates containing ceiling rates applicable to his operations before commencement of commercial operations as required under Section 48 of the Major Port Trusts (MPT) Act and as per Clause 2.9.2. of tariff guidelines of 2008, the Scale of Rates to be framed by this Authority shall be in line with the tariff caps prescribed for the port and included in the bid document subject to indexation explained in Clause 2.8. Such Scale of Rates and statement of conditions shall be notified by this Authority in the Gazette of India as required by the Major Port Trusts Act, 1963.

6.2 As per clause 2.8 of the guidelines for upfront tariff setting for PPP Projects at Major Ports, 2008, the Tariff Caps are to be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year, and the adjusted tariff will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.

6.3 The base year for the upfront tariff and the corresponding annual escalation with effect from 1 April 2013 were already communicated to all the Major Port Trusts including VOCPT vide our letter No. TAMP/12/2009-Misc. dated 2 April 2013.

6.4 As per clause 3 [General Note to Schedule (2)] of the Scale of Rates of the upfront tariff Order dated 23 July 2010 fixing upfront tariff for the facility in reference, tariff caps have to be indexed to inflation to an extent of 60% of the variation in the WPI occurring between 1 January, 2010 and 1 January, of the relevant year. Accordingly, the escalation factor to be applied in the case in reference is 17.63% as per our letter dated 2 April, 2013 read with clause 3 of the Scale of Rates.

7.1 With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i) This Authority has passed an Order No. TAMP/16/2010-TPT dated 23 July 2010 fixing upfront tariff based on the proposal filed by the V.O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) for fixation of upfront tariff for operation of mechanical handling equipments on BOOT basis at VOCPT which was notified in the Gazette of India on 12 August, 2010 vide Gazette No. 201. The VOCPT has awarded the project of upgradation of mechanical handling equipments at berth Nos. I to VI & IX on BOOT basis at VOCPT to M/s. IMCOLA Crane Company Private Limited (ICCPL) and entered into a Concession Agreement on 24 May, 2013 for a period of 10 years.
- (ii) As brought out earlier, Clause 2.9.1. of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff requires the private operator to approach this Authority for notification of the Scale of Rates containing

ceiling rates applicable to his operations before commencement of commercial operations. Accordingly, the ICCPL has approached this Authority with a request to notify the Scale of Rates as required under the Tariff Guidelines of 2008.

- (iii) As reported by the ICCPL, the operator expects that the commercial operations will commence w.e.f. 10 January 2014. Relying on the position reported by ICCPL, this Authority is inclined to entertain the proposal of ICCPL for notification of the Scale of Rates approved in July 2010 subject to adjustment with reference to the indexation of the rates so approved to WPI to the extent of 60%.
- (iv) As per Clause 2.9.2. of the Tariff Guidelines of 2008, the Scale of Rates to be framed by this Authority for the private operator as per Clause 2.9.1 should be in line with the tariff caps prescribed for the Port and included in the bid document, subject to indexation as explained earlier. Article 8.1 of the Concession Agreement (C.A.) entered between the VOCPT and ICCPL governs levy of the tariff at multipurpose berth Nos. I to VI & IX as per the Concession Agreement. As per Article 8.1 of the License Agreement, the Concessionaire i.e. ICCPL shall be entitled to recover tariff from the users of the Project Facilities and Services as per the Tariff Notification annexed as Appendix -12. It is seen that Appendix - 12 appended to C.A. gives reference to the Upfront Tariff approved by this Authority vide Order No.TAMP/16/2010-TPT dated 23 July 2010. It also gives reference to the tariff Order No.TAMP/50/2011-VOCPT dated 19 January 2012.
- (v) As regards the latter Order dated 19 January 2012 referred in Appendix-12 of the Concession Agreement, it is relevant to mention that the VOCPT had filed a separate proposal for fixation of tariff for HMC of 120T capacity. This Authority, however, vide its Order No.TAMP/50/2011-VOCPT dated 19 January 2012 has rejected the said VOCPT proposal and has ordered that the upfront tariff prescribed in the Order No.TAMP/16/2010-TPT dated 23 July 2010 holds good for induction of HMC at VOCPT during the specified five years subject to annual indexation of tariff as mentioned in para 9.1. of the said Order of 23 July 2010. Therefore, the reference of Order No.TAMP/50/2011-VOCPT dated 19 January 2012 given in Appendix-12 of the C.A. does not appear to be relevant for notification of Scale of Rates for ICCPL.
- (vi) With reference to the indexation of the upfront tariff fixed vide Order dated 23 July 2010 as required under Clause 2.8. of the 2008 Guidelines, an escalation factor of 17.63% is applied on the tariff caps notified in July 2010. The ICCPL has drawn up the draft proposed SOR applying the escalation factor of 17.63% on the tariff caps notified in July 2010, along with the conditionalities governing the application of rates as prescribed in the said tariff Order. It is only the tariff items notified vide Order of July 2010 that have been subjected to change in view of the application of applicable escalation factor. For the subsequent years as well, the indexation to the extent of 60% of the WPI occurring between January 2010 and January of the relevant year has to be with reference to the tariff approved vide Order no.TAMP/16/2010-TPT dated 23 July 2010 and not with reference to the indexed Scale of Rates approved in this Order. The General note to Schedule (2) proposed by ICCPL retaining the general note approved in the Order dated 23 July 2010 is, therefore, suitably modified clarifying this position. This is in line with the prescription in the Scale of Rates of other BOT operators governed under 2008 guidelines who have commenced the operations. All the other conditionalities governing the application of the rates as approved in the Scale of Rates of the Order dated 23 July 2010 are retained.
- (vii) As rightly pointed out by the VOCPT, the ICCPL, in its proposed draft Scale of Rates, has not included a note governing calculation of incremental ceiling rates prescribed below the Schedule (II) of charges for hire of Harbour Mobile Cranes for Break-bulk cargo (Steel and Bagged Cargo) under Main Schedule 2 in the Order of July 2010. The note under Schedule-II for Break bulk cargo is reproduced below:

**“Note :** To calculate the incremental ceiling rates as shown above, the base rate was enhanced to 105% for first thousand tonnes. The same methodology shall also be adopted to calculate the rate beyond 7000 tonnes. Likewise, ceiling rates for performance below 5000 tonnes shall be calculated by reducing the base rate accordingly.”

The said note prescribed by this Authority in Order dated 23 July 2010 is inserted in the Scale of Rates for ICCPL approved by this Authority.

- (viii) As per clause 3.8.5 of the 2008 guidelines, if any question arises requiring clarifications or interpretation of the Scale of Rates and the statement of conditions, the matter shall be referred to this Authority and its decision in this regard will be binding on the operator.
- (ix) The ICCPL is expected to perform at least at the performance norms brought out in the bid documents/ concession agreement. The actual performance of the ICCPL will be monitored by this Authority. If any complaint regarding quality of service is received, this Authority may enquire into such allegation



and forward its findings to the VOCPT. If any action is to be taken against the ICCPL, the VOCPT shall initiate appropriate action in accordance with the provisions of the Concession Agreement.

- (x) During the commercial operation at the terminal, within 15 days from the end of every quarter, the ICCPL is directed to submit to this Authority through the VOCPT a report containing the physical and financial performance at berth Nos. I to VI & IX during the preceding three months.

7.2. In the result, and for the reasons given above and based on collective application of mind, this Authority approves the Scale of Rates for operation of mechanical handling equipments at Berth Nos. I to VI & IX to be operated by the ICCPL at VOCPT attached as **Annex**.

7.3. The Scale of Rates notified for ICCPL will come into force from the date of commencement of commercial operations by ICCPL at VOCPT.

**T.S. BALASUBRAMANIAN**, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/13]

**ANNEX**

**IMCOLA Crane Company Private Limited**  
**SCALE OF RATES**

**1.1 Definitions – General**

In this Scale of Rates, unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (i) **“Coastal vessel”** shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the competent authority.
- (ii) **“Foreign-going vessel”** shall mean any vessel other than coastal vessel.
- (iii) **“Day”** shall mean the period starting from 6 a.m. of a day and ending at 6 a.m. on the following day.

**1.2 General Terms & Conditions**

- (i) (a) The cargo related charges for all coastal cargo other than crude including POL, Iron ore and Iron pellets and thermal coal should not exceed 60% of the normal cargo related charges.
- (b) In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship shore transfer.
- (c) Cargo from a foreign port which reaches an Indian Port “A” for subsequent transshipment to Indian Port “B” will be levied the concession charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from/to Indian Ports carried by vessels permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
- (d) The charges for coastal cargo vessels shall be denominated and collected in Indian rupee.
- (ii) Interest on delayed payments / refunds.
  - (a) The user shall pay penal interest on delayed payments of under this Scale of Rates. Likewise, the terminal operator shall pay penal interest on delayed refunds.
  - (b) The rate of penal interest will be 2% above the prime lending rate of the State Bank of India.

- (c) The delay on refunds will be counted only 20 days from the day of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.
- (d) The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the terminal operator. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services where payment of charges in advance is prescribed as a condition in the scale of rates.
- (iii) All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.
- (iv) No claims for refund shall be entertained unless the amount refundable is `100/- or more. Likewise, the terminal operator shall not raise supplementary bills for short collection, if the amount due to the terminal operator is less than `100/-.
- (v)
  - (a) The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels: likewise, rebates and discounts are floor levels. The terminal operator may, if they so desire, charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts.
  - (b) The terminal operator may also, if they so desire rationalise the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalisation gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling levels.
  - (c) The terminal operator should notify the public such lower rates and / or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.
- (vi) Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to terminal operator.

## 2. CHARGES FOR HIRE OF HARBOUR MOBILE CRANES:

### (I) For Dry Bulk Cargo

Average daily crane performance (in Metric Tonne)	Rate per tonne (in `)	
	Foreign	Coastal
9500-10499	29.69	17.81
10500-11499	31.43	18.86
11500-12499	33.18	19.91
12500	34.92	20.95
12501-13500	36.67	22.00
13501-14500	38.41	23.04
14501 – 15500	40.15	24.09

**Note:** To calculate the incremental ceiling rates as shown above, the base rate was enhanced to 105% for first thousand tonnes and for the 2<sup>nd</sup> thousand tonnes the rate was enhanced to 110% of the base rate. The rate for third thousand tonnes was arrived by enhancing the base rate by 115%. The same methodology shall also be adopted to calculate the rate beyond 15500 tonnes. Likewise, ceiling rates for performance below 9500 tonnes shall be calculated by reducing the base rate accordingly.

### (II) For Break-bulk cargo:

#### (A) Steel and Bagged Cargo

Average daily crane performance (in Metric tonne)	Ceiling rate per tonne (in `)	
	Foreign	Coastal
5000-5999	65.04	39.02
6000	68.46	41.08
6001-7000	71.88	43.13

**Note :** To calculate the incremental ceiling rates as shown above, the base rate was enhanced to 105% for first thousand tonnes. The same methodology shall also be adopted to calculate the

rate beyond 7000 tonnes. Likewise, ceiling rates for performance below 5000 tonnes shall be calculated by reducing the base rate accordingly.

(B) Others

Average daily crane performance (in Metric tonne)	Ceiling rate per tonne (in `)	
	Foreign	Coastal
2750-3749	104.11	62.47
3750	109.60	65.76
3751-4750	115.08	69.05

**Note :** To calculate the incremental ceiling rates as shown above, the base rate was enhanced to 105% for first thousand tonnes. The same methodology shall also be adopted to calculate the rate beyond 4750 tonnes. Likewise, ceiling rates for performance below 2750 tonnes shall be calculated by reducing the base rate accordingly.

**Notes :**

- (i) The formula for calculation of average berth-day out put is as follows:  

$$\frac{\text{Total Quantity loaded / unloaded by the HMC}}{\text{Total time taken from vessel commencement to completion}} \times 24 \text{ hours}$$
- (ii) According to the average berth-day output for the vessel from commencement to completion of loading / discharge of cargo, the appropriate rate of crane hire charge will be chosen for recovery from port users for the full quantity of cargo loaded / discharged.
- (iii) If one HMC works with another HMC or ELL crane/s, the Berth-day output for the crane will be ascertained on the basis of the quantity as recorded by the HMC's load meter.
- (iv) In case of breakdown of the crane for more than one hour till the vessel leaves the berth, the quantity handled by HMC will be determined taking into account cargo loaded / discharged prior to break-down divided by crane working hours and multiplied by 24.
- (v) In case of stoppages of operation of HMC for more than two hours at a stretch for reasons not attributable to the HMC, appropriate allowance will be allowed to the crane while calculating the total time of crane operation in the vessel. Stoppages of HMC for less than 2 hours will not be taken into consideration for the above purpose. No allowance will be allowed for stoppages attributable to the HMC. All stoppages in loading / unloading operations during working of HMC are required to be certified by the TPT Officers or any other agency nominated by the TPT in the daily vessel performance report.
- (vi) In case shifting of a vessel becomes necessary due to breakdown / non-performance of HMC, the shifting charges of the vessel from berth to anchorage will be recovered from the crane operator in addition to a penalty of `1,00,000/- (Rupees one lakh only). The shifting charges so recovered will be refunded to the vessel's agent while the penalty will be retained by the port.
- (vii) In case of dispute on the average output, the decision of the port trust will be final and binding.

**3. GENERAL NOTE TO SCHEDULE (2) ABOVE :**

The tariff caps prescribed in the Scale of Rates of IMCOLA Crane Company Private Limited takes into consideration the upfront tariff approved by the Authority vide Order No. TAMP/16/2010-TPT dated 23 July 2010 and applying indexation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2010 and 1 January of the relevant year. For the subsequent years as well, upfront tariff approved in the Order No.TAMP/16/2010-TPT dated 23 July 2010 will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2010 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.